स्टेशन की निर्माणाधीन मुंह-चिढ़ाती बिल्डिंग के सामने मंत्री कृष्णपाल ने प्लेटफ़ार्म की सीढ़ी का किया उद्घाटन

फ़रीदाबाद (म.मो.) बीते बीस सालों से पलवल, असावटी, बल्लभगढ़, एनआईटी व ओल्ड फरीदाबाद के स्टेशनों पर यात्रियों के बढ़ते दबाव के बावजूद, एक प्लेटफार्म से दूसरे पर जाने के लिये किसी भी सरकार ने पर्याप्त पुल बनवाने की जरूरत नहीं समझी। बीते पांच सालों में कृष्णपाल की मोदी सरकार ने इन शहर वासियों के लिए धेले भर का भी काम नहीं करके दिया। लेकिन अब चुनाव सिर पर खड़े देखकर ओल्ड फरीदाबाद के रेलवे स्टेशन पर एक नये पुल का शिलान्यास किया है, जो बनकर कब तैयार होगा राम जाने। हां पुराने पुल की सीढ़ियों की जगह स्वचालित सीढ़ियां लगाकर मंत्री जी जरूर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। इस तरह की सीढ़ियां आज आम बात हो चुकी हैं। मेट्रो रेल ने इसी शहर में अपने कुल 11 स्टेशनों पर 55 से अधिक स्वचालित सीढ़ियां बरसों पहले बिना किसी शोर-शराबे व ड्रामेबाजी के लगवा दी थी। कृष्णपाल इस एक सीढ़ी का ही ढोल पीटकर चुनाव जीतने की जुगत में हैं। इन्हीं सीढ़ियों के पास स्टेशन की वह नई बिल्डिंग है जिसका निर्माण बीते आठ-नौ साल से चल रहा है। शुरू में इसकी अनुमानित लागत 10 करोड़ थी जो अब साढ़े बारह करोड़ से भी अधिक हो चुकी है और जब तक यह तैयार हो पायेगी न जाने कितने करोड़ की पड़ेगी? इसी तरह चौथी रेलवे लाइन का बचा हुआ 15-20 किलोमीटर का छोटा टुकड़ा भी कृष्णपाल की उस सरकार से पूरा नहीं हो पा रहा जिसका पीएम हर रोज 20 घंटे काम करता है और आज तक एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। मजे की बात तो यह है कि इतना सब होते हुए भी कृष्णपाल को स्टेशन पर आने में कतई कोई शर्म महसूस नहीं हुई।

फरीदाबाद रेलवे स्टेशन : स्मार्ट होने की अंतहीन प्रतीक्षा!

सर्वविदित है कि चौथी लाइन न बिछ पाने के कारण इस मार्ग पर चलने वाले यात्रियों खासकर दैनिक यात्रियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ट्रेनें लेट तो होती हैं। कम से कम 50 दिन शटल ट्रेनों को रद्द भी कर दिया जाता है, कभी धुंध के बहाने तो कभी बरसात के बहाने तो कभी मरम्मत के बहाने।

पीएम मोदी के लाडले अनिल अम्बानी से यह सरकार हाइवे पार करने के लिये 20 पुलों की जगह बमुश्किल एक ही पुल बनवा पाई है, वह भी तब जब नेहरू कॉलेज के छात्रों ने एक के बाद एक प्रदर्शन का सिलसिला जारी रखा। इस पर भी स्वचालित सीढ़ियों की बजाये साधारण सीढ़ियां ही लगाई गयी हैं। करोड़ों रुपये टोल टैक्स लूटने वाले इस लुटेरे अंबानी को कांग्रेस सरकार ने भी तो लूट का पट्टा दिया ही था, मोदी सरकार ने उसकी लूट बढ़ाने के लिये गदपुरी पर भी एक टोल नाका बनवा दिया है।

FASHION.IN

Available all types of ladies cotton kurties, Fancy Kurties, Jegin, legin, Fancy Top, T-Shirts, Trousers and imported material in wholesale price.

SPECIALITY IN FANCY TOP & FANCY KURTIES

लेडीज कपड़ों पर भारी छूट
एक बार सेवा का मौका अवश्य दें

Address : 5M/22, N.I.T. FARIDABAD NEAR DAYANAND WOMEN COLLEGE, ST. JOSEPH CONVENT SCHOOL ROAD . 9911489490

सुधी पाठकों से अपील

31 वर्षों से 'मज़दूर मोर्चा' वैकल्पिक मीडिया के तौर पर अपने सुधी पाठकों को वह समाचार, विचार एवं जन उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करता आ रहा है जिसे अन्य मीडिया छिपाने का प्रयास करता है। सुधी पाठक इतना तो समझ ही गये होंगे कि यह छोटा सा अखबार किसी भी राजनीतिक अथवा व्यवसायिक धड़े से जुड़ा नहीं है। जनहित में जो भी प्रकाशित करने लायक सामग्री हो पाती है उसे लोग़ों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है।

बिना विज्ञापनों के, केवल पाठकों के सहयोग से चलने वाला यह छोटा सा अखबार आपको और अधिक बेहतर व निरंतर सेवा देता रहे इसके लिये आप से निवेदन है कि इसमें अपना आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। 'मज़दूर मोर्चा' नियमित रूप से खरीदकर पढ़ने वाले पाठक तो अपना योगदान दे ही रहे हैं, इलेक्ट्रोनिक माध्यम से अखबार पढ़ने वाले पाठकों से विशेष अनुरोध है कि वे भी इसमें अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करें। वार्षिक सहयोग के तौर पर 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये की धनराशि सामर्थ्य अनुसार 'मज़दूर मोर्चा' के निम्नलिखित खाते में डाले जा सकते हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में

खाता संख्या : 451102010004150

IFSC CODE : UBIN0545112

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोड़ा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5
2. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड
3. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
4. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे
5. राम खिलावन बल्लबगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने
6. हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास
7. जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207

गतांक की चीर-फ़ाड़

युद्ध उन्माद से वोट उन्माद तक

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

मजदूर मोर्चा के 24 फरवरी-2 मार्च 2019 के अंक में राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक तथा सामाजिक मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशित हुए है। कश्मीर में जब सीआरपीएफ के जवान बसों में सवार होकर जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे तब उन पर आत्मघाती जघन्य हमला किया गया, जिसमें 44 जवान शहीद हो गए। इस पर सभी भारतीय स्तब्ध रह गए और लोगों के दिलों में गहरा रोष छा गया। सबसे तकलीफदेह बात थी कि ये जवान किसी युद्ध मोर्चे पर तैनात नहीं थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा से जगह-जगह पर शहीदों को श्रद्धाजंलि देने के लिए श्रद्धाजंलि सभाएं आयोजित करने और वहां चुनाव चिन्ह 'कमल का फूल' प्रदर्शित करने को कहा। संघ परिवार, भाजपा, मोदी, सरकार व मीडिया ने देश में राष्ट्रवाद के नाम से युद्ध का सा वातावरण बना दिया और साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न कर दिया।

उत्तर भारत के अधिकांश शहरों में 'उन्मादी नारों के साथ जुलूस निकाले जा रहे हैं, जिसकी 'शक और गहरा हो रहा है' में विवेचना की गई है। देश में कश्मीरियों के विरुद्ध वातावरण बन रहा है। संघ परिवार की विभिन्न संस्थाओं द्वारा उत्तर भारत में पढ़ रहे कश्मीरियों विद्यार्थियों के बहिष्कार का अभियान चलाया जा रहा है तथा उनको उत्पीड़ित किया जा रहा है। मेघालय के राज्यपाल तथागत राय ने भी कश्मीरियों के विरुद्ध विवादित बयान दिया है परन्तु मोदी सरकार ने राज्यपाल समेत किसी के भी विरुद्ध कोई कार्यवाई नहीं की।

पुलवामा में शहीद हुए जवानों की शहादत पर सरकारी घोषणा के बावजूद शहीद परिवारों को कुछ नहीं मिला। इस झूठ व खोखलेपन की 'शहीद रतन के परिवार से मिली भाकपा मासे टीम, झूठे और खोखले घोषणाओं में व्यस्त है सरकार' में पोल खोली गई है। शहादत के 6 दिन बाद भी भागलपुर के शहीद जवान रतन कुमार ठाकुर के परिवार को कोई सहायता नहीं मिली है।

'पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों का लहू राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ/भाजपा से मांग रहा जवाब' में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार के शासनकाल में खूंखार आंतकवादियों अजहर मसूद, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जारगर को भारतीय जेल से रिहा करके पाकिस्तान जाने देना, प्रधानमंत्री मोदी का पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के प्रति प्रेम, अचानक लाहौर जाकर नवाज शरीफ की नातिन के निकाह में मोदीजी का शामिल होना, सेना व पुलिस का खोखला दावा कि कश्मीर में उग्रवाद कुचल दिया गया, सुरक्षा कर्मियों की आवाजाही के लिए विमानों का उपयोग न करना आदि के संदर्भ में आरएसएस व भाजपा की जवाबदेही का सटीक विश्लेषण किया गया है।

पुलवामा में आत्मघाती हमला करने वाला अहमद पाकिस्तानी नहीं बल्कि भारतीय कश्मीरी था। इससे महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों स्थानीय पढ़े-लिखे व सम्पन्न कश्मीरी अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार होते हैं। इस मुद्दे पर गंभीर बहस करने की आवश्यकता है जिसको अक्सर सरकारें नजर अंदाज करती आ रही है। 'पुलवामा हमले के बाद कश्मीर के असली मुद्दे को फिर नजर अंदाज किया जा रहा है' में इस समस्या के मूल मुद्दे का समाधान करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

गौरतलब है कि संघ परिवार, भाजपा व प्रधानमंत्री मोदी पुलवामा में जवानों की शहादत का चुनावी लाभ उठाने के लिए राजनीतिकरण कर रहे हैं जबकि कुछ राजनीतिक प्रयासों के फलस्वरूप वाजपेयी और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में स्थानीय स्तर पर आंतकियों की भर्ती का सिलसिला कमजोर पड़ा था और मनमोहन सरकार के कार्यकाल में घाटी के अंदर कश्मीर मूल के आंतकी गिने-चुने रह गए थे। परन्तु आज यह सैकड़ों में पहुंच गई हैं मोदीजी के कार्यकाल में बिना किसी युद्ध के कश्मीर में 1513 लोग मारे जा चुके हैं। कश्मीर समस्या के हल के लिए ठोस राजनीतिक पहल करने की आवश्यकता है, न कि दोबारा सिर्फ सैनिक नजरिए को देखने की।

मजदूर मोर्चा में प्रकाशित उपरोक्त समाचारों में पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले के विभिन्न महत्वपूर्ण पक्षों का विश्लेषण किया गया है, जबकि अन्य समाचार पत्रों ने इन पक्षों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है।

संघ परिवार व अखिल भारतीय विद्याथी परिषद् (एबीवीपी) द्वारा जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) में साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न करने के लिए नाकाम कोशिश की गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा अलीगढ़ के अध्यक्ष मुकेश सिंह लोधी तथा रिपब्लिक चैनल के पत्रकारों की मिलीभगत से एएमयू के 14 छात्रों के खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाकर एफ आईआर दर्ज करवाई गई, परन्तु उन छात्रों के खिलाफदेशद्रोह का कोई सुबूत न मिलने पर अलीगढ़ के एसपी द्वारा देशद्रोह की धारा हटा दी गई, जिसका 'अलीगढ़ पुलिस ने कहा, एएमयू के छात्र देशद्रोही नहीं है- देश के कथित राष्ट्रीय हिन्दूवादी मीडिया की पोल खुली' में खुलासा किया गया है। इस एएमयू प्रकरण से हिन्दूवादी मीडिया 'रिपब्लिक भारत चैनल' तथा संघ परिवार की शर्मनाक भूमिका का पर्दाफाश हो गया है।

2006 के वनाधिकार कानून के तहत 2005 से पूर्व वन क्षेत्र के निवासी प्रत्येक परिवार को चार एकड़ भूमि देने का प्रावधान किया गया था। लेकिन 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 21 राज्यों को आदेश दिया कि वे अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को जंगल की जमीन से बेदखल करके जमीन खाली करवाए। इससे देश के 11 लाख से अधिक आदिवासियों का जीने का अधिकार छिन गया है। यह नियमगिरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के खुद के निर्णय के खिलाफ है, क्योंकि वनाधिकार कानून के तहत दावों की प्रक्रिया को समाप्त किए बगैर बेदखली अंसवैधानिक है जिसकी 'सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को झारखंड के 28 हजार आदिवासी परिवारों पर बेघर होने का खतरा में खुलकर चर्चा की गई है। झारखंड सरकार ने इस फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पेटिशन डालने का निर्णय किया गया है तथा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्यप्रदेश सरकार को भी रिव्यू पेटिशन डालने का निर्देश दिया है। केन्द्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर उक्त आदेश में बदलाव करने को कहा जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए मान गई है।

क्यों हुआ आईपीएस जसवीर सिंह का निलंबन-खुद पर रासुका लगाने वाले पुलिस अफसर को कैसे बरदाश्त करता योगी-आईपीएफकाडर को बर्बाद करने की दूसरी मिसाल बना यूपी' में गुजरात में नरेन्द्र मोदी को बेनकाब करने वाले आईपीएस संजीव भट्ट तथा रजनीश राय को गिरफ्तार कराने की तर्ज पर यूपी के मुख्यमंत्री आदित्य नाथ योगी द्वारा अपना पुराना बदला लेने के लिए आईपीएस जसवीर सिंह को निलंबन करने की वजह तथा जसवीर सिंह के कैरियर की विवेचना की गई है।

आज के राजनीतिक हालात में आईपीएस तथा आईएएस अफसर सत्ता के नजदीक पहुंचने के चक्कर में अक्सर अपने मुख्यमंत्री और मंत्री का गलत आदेश बजाने को तत्पर रहते हैं, जिसके कारण ईमानदार अफसरों को हर राज में भुगतान करना पड़ता है।

लोकसभा चुनाव में फरीदाबाद क्षेत्र से संभावित प्रत्याशियों कांग्रेस से अवतार सिंह भड़ाना, भाजपा से कृष्णपाल गूजर तथा जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) से हर्ष कुमार की राजनीति की 'अवतार-कृष्णपाल, यानी सांपनाथ बनाम नागनाथ-अवतार भड़ाना या कृष्णपाल गूजर.....फरीदाबाद की जनता को उल्लू बनाने की राजनीति....एक को तो चुनना ही पड़ेगा' तथा 'लोकसभा चुनाव की आई बहार, हर्ष कुमार ने भी भरी बड़ी हुंकार' में चर्चा की गई है।

यूपी के मुख्यमंत्री योगी द्वारा हनुमान को दलित बताने पर 'अभी तो हनुमान जी दलित हुए हैं, 2019 तक रावण मुसलमान न हुआ तो बताना' तथा पुलवामा हमले के संदर्भ में आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागत की भूमिका पर 'हैलो!! मोहन भागवत! मुझे सेना की जरूरत है - मुझे तीन दिन का समय दें!! कासगंज, मुजफ्फरनगर कहां भेजना है?? नहीं-नहीं एसओसी पर!!! गलत नम्बर है।' कार्टूनों द्वारा योगी व भागवत की नीतियों पर उपयुक्त तंज कसा गया है।